Kamal.Sandesh
kamalsandesh.org
KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-19
01-15 अक्टूबर, 2024 (पाक्षिक)
₹20

'जम्मू-कश्मीर स्थायी शांति की ओर तेजी से बढ़ चला है'

एनडीए सरकार 3.0 के 100 दिन

हरियाणा 'संकल्प पत्र' जारी

'नॉनस्टॉप हरियाणा' के लिए समर्पित भाजपा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 17 सितंबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 'सेवा पखवाड़ा' एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण

जम्मू में 22 सितंबर, 2024 को आयोजित 'बौद्धिक सम्मेलन' में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते जम्मू-कश्मीर भाजपा के नेतागण

रोहतक में 19 सितंबर, 2024 को आयोजित 'कार्यकर्ता सम्मेलन' में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते हरियाणा भाजपा के नेतागण

मेंढर (जम्मू-कश्मीर) में 21 सितंबर, 2024 को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

श्री बंशीधर नगर (झारखंड) में 21 सितंबर, 2024 को परिवर्तन सभा के दौरान अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **हरियाणा की छवि 'नॉन-स्टॉप डेवलपमेंट' की बनी है : जगत प्रकाश नड्डा**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 सितंबर, 2024 को हरियाणा के रोहतक स्थित प्रदेश मीडिया सेंटर में...

09 **कांग्रेस-एनसी-पीडीपी ने सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया, लेकिन भाजपा सबको जोड़ रही है : नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर...

11 **भाजपा सरकार में हरियाणा घोटालामुक्त और विकासयुक्त हो गया: जगत प्रकाश नड्डा**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा...

14 **'प्रधानमंत्री मोदीजी ने देश के संकल्पों को सिद्धि में बदला है'**
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर...

31 **प्रधानमंत्री ने ओडिशा में महिला-केंद्रित सबसे बड़ी योजना 'सुभद्रा' का किया शुभारंभ**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार...

लेख

एकात्म मानववाद: समाज के सर्वांगीण विकास की कुंजी / **डॉ. सुभाष सरकार** 22

सरकार के 100 दिन : विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम / **अरुण सिंह** 26

100 दिनों का परिवर्तनकारी नेतृत्व: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी शासन का प्रमाण / **तरुण चुघ** 28

सिखों को पुनः निराश किया / **हरदीप सिंह पुरी** 32

अन्य

अब जम्मू-कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं, बल्कि टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है: राजनाथ सिंह 12

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप दिया: अमित शाह 13

'भाजपा सरकार सभी अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देगी' 13

'स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता' 16

गरीब कल्याण, सुरक्षा और गौरव के 100 दिन 17

मोदी स्टोरी 25

कमल पुष्प 25

प्रधानमंत्री ने झारखंड में कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया 33

प्रधानमंत्री ने भारतीय पैरा-एथलीटों से की मुलाकात 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को स्वीकृति दी है। इससे न केवल किसानों को अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।

(18 सितंबर, 2024)

जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी ने यह रिपोर्टकार्ड की संस्कृति स्थापित की है। 'हर खेत को पानी' योजना के तहत हमने हरियाणा के प्रत्येक कृषि भूमि को सिंचित किया है। ब्याज मुक्त कृषि ऋण से 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे, यह व्यवस्था की गई है। कृषि, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, यातायात, खेल, महिला सशक्तीकरण आदि सभी विषयों पर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। यह हमारा रिपोर्टकार्ड है।

(19 सितंबर, 2024)

अमित शाह

जम्मू-कश्मीर के चुनाव में इस बार जनता, यहां आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और युवाओं के हाथों में हथियार थमाने वाले जेकेएनसी, कांग्रेस और पीडीपी को नकार कर, शांति और विकास के प्रतीक कमल के फूल का बटन दबाने जा रही है।

(21 सितंबर, 2024)

राजनाथ सिंह

मोदीजी के नेतृत्व में हमारी सरकार जहां पहले ओवर से ही तेज़ी से रन बनाकर देश का स्कोर बढ़ा रही है, वहीं विपक्ष नो बॉल और वाइड बॉल फेंकने में ही देश का बेशक़ीमती समय और संसाधन बर्बाद कर रहा है।

(17 सितंबर, 2024)

बी.एल. संतोष

रॉस, नील और हैवलॉक द्वीपों का नाम बदलकर शहीद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वराज द्वीप करने के बाद अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर 'श्री विजयपुरम' कर दिया है। एक और औपनिवेशिक निशानी को मिटा दिया गया।

(14 सितंबर, 2024)

शिवराज सिंह चौहान

ICAR- राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में अभी लाख की खेती से जुड़े 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने तय किया है कि इस साल से 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वह प्रशिक्षण प्राप्त कर ज्यादा लाभ कमा सकें।

(20 सितंबर, 2024)

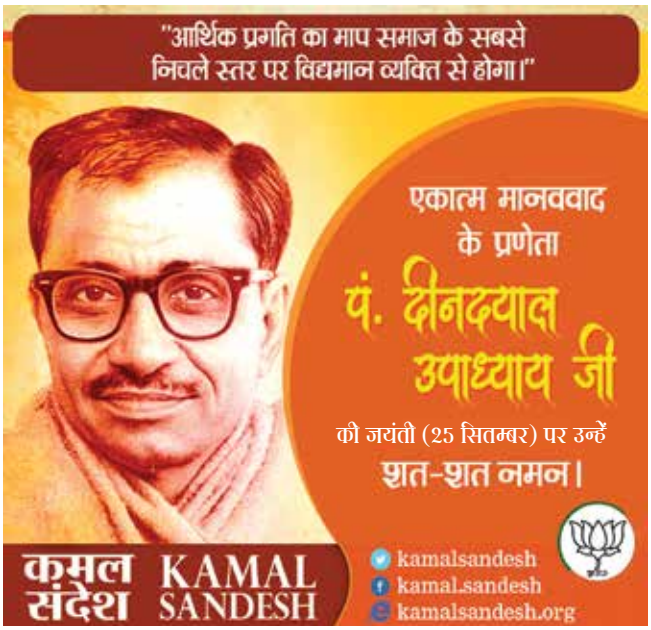

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
विजयदशमी (12 अक्टूबर)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

अद्वितीय उपलब्धियों से भरा मोदी सरकार 3.0 के प्रथम 100 दिन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा 'सेवा पखवाड़ा' के शुभारंभ के साथ ही देशभर में करोड़ों भाजपा कार्यकर्ता जनसेवा को समर्पित रहने के संकल्प के प्रति पुनः सन्नद्ध हुए हैं। आज भाजपा देश में एकमात्र राजनैतिक दल है जो 'सेवा कार्य' में विश्वास करता है और जिसके करोड़ों कार्यकर्ता देशभर में निरंतर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों में समर्पित भाव से लगे हुए हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया अविस्मरणीय सेवा कार्य अत्यंत विकट परिस्थिति में भी 'सेवा भाव' बनाए रखने का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। हर वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्तूबर, गांधी जयंती तक पूरे देश में भाजपा 'सेवा पखवाड़ा' मनाती है। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, बस्तियों में 'सेवा-कार्य' आयोजित किए जाते हैं। जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वयं का जीवन ही हर कार्यकर्ता को गरीबों, वंचितों, पीड़ितों एवं शोषितों की अथक सेवा कर राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं 'सेवा पखवाड़ा' जन-जन में 'सेवा-भाव' जागृत करने का एक अवसर भी है।

मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों में न केवल 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, बल्कि आने वाले दिनों में 'विकसित भारत' के पथ को प्रशस्त करने के लिए अवसंरचनाएं विकसित करने के लिए अनेक परियोजनाओं की घोषणाएं हुई हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार का पहला 100 दिन अद्भुत उपलब्धियों एवं अद्वितीय सिद्धियों से भरा हुआ है। मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों में न केवल 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, बल्कि आने वाले दिनों में 'विकसित भारत' के पथ को प्रशस्त करने के लिए अवसंरचनाएं विकसित करने के लिए अनेक परियोजनाओं की घोषणाएं हुई हैं। सड़क, रेल, बंदरगाह एवं हवाई मार्ग के विकास पर सरकार की प्रतिबद्धता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसका ध्यान 62,500 कि.मी. सड़क एवं पुल का निर्माण कर 25,000 ऐसे गांवों को भी जोड़ना है जो अब तक जुड़े नहीं हैं। 936 कि.मी. के आठ नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडॉर, आठ नई रेल लाइन परियोजनाएं, नए हवाई अड्डे, बेंगलुरू एवं पुणे में मेट्रो का विस्तारीकरण एवं थाणे इंटीग्रल रोड परियोजनाओं के स्वीकृत किए जाने से भारत में विश्व-स्तरीय अवसंरचना विकसित करने के मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को समझा जा सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने के साथ ही देश के 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित हो गए। इसके साथ ही अब तब किसानों को इस योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। खरीफ फसल के एमएसपी घोषित होने से देश में 12 करोड़ किसान परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपयों का लाभ प्राप्त होगा। किसानों के लिए घोषित अनेक पहलों के साथ मध्य वर्ग को भी बड़ी राहत मिली है। करों में राहत, पारिवारिक पेंशन में छूट, आयकर के नियमों की व्यापक समीक्षा तथा सरकारी कर्मचारियों को 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' का उपहार मध्य वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया है। 3 करोड़ पक्के घर, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जून से अगस्त, 2024 के मध्य 2.5 लाख घरों को जोड़ना, पर्यावरण को ध्यान में रखकर ई-बस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता तथा युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक पहल हर क्षेत्र में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण की बात हो या स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक, सुशासन एवं कानून-व्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति एवं आपदा प्रबंधन, हर क्षेत्र में अनेक अभिनव पहल लिए गए हैं, जो आने वाले दिनों में 'विकसित भारत' के स्वप्नों को साकार करेंगे।

जम्मू-कश्मीर एवं हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रथम चरण में हुआ भारी मतदान जहां लोकतंत्र की जीत है, वहीं आतंकवाद पर कड़ा प्रहार है। यह जम्मू-कश्मीर की जनता की जीत है जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आए तथा आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा लगाया है। यह शांति, समृद्धि एवं प्रगति की जीत है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

हरियाणा विधानसभा चुनाव : भाजपा संकल्प पत्र जारी

हरियाणा की छवि 'नॉन-स्टॉप डेवलपमेंट' की बनी है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 सितंबर, 2024 को हरियाणा के रोहतक स्थित प्रदेश मीडिया सेंटर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 'संकल्प पत्र' को जारी करते हुए बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा हरियाणा के लिए किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बदोली, केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने संकल्प पत्र या मेनिफेस्टो को महत्वहीन बना दिया। कांग्रेस ने लंबे समय में मेनिफेस्टो की महत्ता को खत्म कर दिया। उनके लिए मेनिफेस्टो महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह कागज महज एक परम्परा को पूरा करना है। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो के माध्यम से केवल जनता के साथ छलावा किया है। श्री नड्डा ने कहा कि दस साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी वाले प्रदेश की थी। पहले पर्ची पर नौकरी लगती थी और इसकी जांच भी हुई थी, इसमें लोग पकड़े भी गए। उसी तरह दस साल पहले हरियाणा जमीन घोटाले के लिए चर्चित था। किसानों की जमीन हड़प ली जाती थी और उसे अन्य कार्यों के उपयोग के लिए कागजात बना दिया जाता था। कांग्रेस और उन विपक्षी पार्टियों की असली मेनिफेस्टों ऐसे ही काम करने के लिए था। दस साल पहले हरियाणा की छवि भ्रष्टाचार वाले प्रदेश की थी। कांग्रेस किसानों की बात करती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती थी। श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति लायी। अर्थात्, भाजपा जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। भारतीय जनता पार्टी 'नॉन स्टॉप हरियाणा' की बात करती है और भाजपा हरियाणा में उसी तीव्र गति से काम भी कर रही है, लेकिन इसे 'नॉन स्टॉप' बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हरियाणा की जनता की है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा

था वो भी करके दिया है और जो कहेंगे वो भी पूरा करके देंगे।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 37 हज़ार रुपए थी, आज यह दोगुनी बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है, पहले हरियाणा की निर्यात दर 68 हजार करोड़ रुपए थी, जो अब 3 गुना बढ़कर 2.50 लाख करोड़ रुपए हो गई है। हरियाणा में पहले केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज ये संख्या दुगनी होकर 15 हो चुकी है, पहले मेडिकल कॉलेज में केवल 700 सीटें हुआ करती थीं, जो आज बढ़कर 2,085 हो चुकी हैं। वर्ष 2014 में हरियाणा के केवल 538 गांवों को ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, मगर आज राज्य के 5800 गांवों तक बिजली को पहुंचाया जा रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार में फसल के मुआवजों के नाम पर केवल 1 हज़ार 158 करोड़ रुपए दिए जाते थे, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने 12 हज़ार 500 करोड़ रुपए देने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में फसल के नुकसान का मापदंड केवल 6 हज़ार रुपए प्रति एकड़ था, भाजपा सरकार ने इसे 2.5 गुना बढ़ाकर बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए प्रति एकड़ करने का काम किया है। पहले वृद्धजन पेंशन केवल 1 हज़ार रुपए हुआ करती थी, भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाकर 3 हज़ार रुपए करने का काम किया है। झूठे किसानों के हितैषी कांग्रेस नेता जो अभी एमएसपी की गारंटी मांगते घूम रहे हैं, हरियाणा में जब उनकी सरकार थी, तो केवल 8 फसलों की खरीद एमएसपी पर किया करती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसका दायरा 24 फसलों तक बढ़ाया है। भाजपा ने जो नहीं कहा था, वो भी पूरा किया है।

वर्ष 2014 में हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 37 हज़ार रुपए थी, आज यह दोगुनी बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है, पहले हरियाणा की निर्यात दर 68 हजार करोड़ रुपए थी, जो अब 3 गुना बढ़कर 2.50 लाख करोड़ रुपए हो गई है। हरियाणा में पहले केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज ये संख्या दुगनी होकर 15 हो चुकी है, पहले मेडिकल कॉलेज में केवल 700 सीटें हुआ करती थीं, जो आज बढ़कर 2,085 हो चुकी हैं। वर्ष 2014 में हरियाणा के केवल 538 गांवों को ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, मगर आज राज्य के 5800 गांवों तक बिजली को पहुंचाया जा रहा है

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्ष 2014 एवं वर्ष 2019 के संकल्प पत्र में किए गए वादों को शत-प्रतिशत पूर्ण किया है और आज तीसरी बार भाजपा जनता का आशीर्वाद मांगने आई है। 10 साल पहले नेता अपने पुराने वादों पर बातें नहीं करते थे, अपने काम का हिसाब नहीं रखते थे। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में रिपोर्टकार्ड की संस्कृति की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की भूमि को सिंचित करने का काम किया है, ये किसान की बदलती किस्मत का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। भाजपा का संकल्प है कि 3 लाख किसानों को ब्याज मुक्त किसान ऋण दिया जाएगा, किसानों के लिए मंडियों में 10 रुपए में भोजन की थाली की व्यवस्था की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दिल्ली-सोनीपत-पानीपत के लिए रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की गई है। भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे लाइन भी हरियाणा के रोहतक में ही है। हिसार में एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जिससे देश के अन्य शहरों में आवागमन में आसानी हुई है। हरियाणा के युवाओं के लिए स्टार्ट-अप मिशन की भी शुरुआत की गई है। विवाह शगुन योजना के तहत महिलाओं को जो पहले वार्षिक आय का भुगतान होता था, उसको भी बढ़ाकर 1.8 लाख रुपए किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के कर हस्तांतरण को 4 गुना बढ़ा दिया है। इसी तरह ग्रांट एण्ड एड को भी 3.5 गुना बढ़ाकर 70 हजार करोड़ कर दिया गया। फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए। 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर तक जल पहुंचाने का वादा भी हरियाणा की भाजपा सरकार ने पूरा किया है। आज दिल्ली से रोहतक आने में केवल डेढ़ घंटे का समय लगता है, 10 वर्षों पूर्व किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। रेवाड़ी में एम्स का कार्य शुरू हो गया है। गुरुग्राम में मेट्रो को बढ़ाया जा रहा है। HIRA यानी

संकल्प पत्र के मुख्य बिंदु

- सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्रति माह 2100 रुपये दिए जाएंगे।
- आइएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 अत्याधुनिक औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे और आस-पास के गांवों के 50 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी।
- चिरायु आयुष्मान की 5 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया जाएगा और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए अलग से 5 लाख रुपये की व्यवस्था की जाएगी।
- 24 फसलों की एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी।
- 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची-पर्ची के पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने का कार्य किया जाएगा, 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे।
- शहरी और ग्रामीण इलाकों में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे, ताकि कोई भी गरीब परिवार बिना पक्की छत के रहने को मजबूर न रहे।
- सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था की जाएगी, सरकार व प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- ओलंपिक्स के लिए हर जिले में नर्सरी बनाई जाएंगी।
- हर घर गृहिणी योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देना जारी रखा जाएगा।
- कॉलेज जानेवाली बालिकाओं को अव्वल बलिका योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी दी जाएंगी।
- अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए युवाओं को हरियाणा की भाजपा सरकार सरकारी नौकरी की गारंटी देगी।
- केएमपी के साथ-साथ ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर का निर्माण पूरा किया जाएगा। पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़, खरखौदा से चंडीगढ़ और मथुरा तक वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत दिल्ली से पलवल, धारूहेड़ा, रोहतक और पानीपथ तक रैपिड रेल को केन्द्र की सहायता से शुरू किया जाएगा।
- बाटा चौक से सेक्टर 56 गुरुग्राम के लिए भी मेट्रो सेवा को शुरू किया जाएगा।
- पिछड़ी हुई 36 बिरादरियों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाकर उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी।
- डीए-पेंशन के साइंटिफिक फार्मूला के आधार पर सामाजिक मासिक पेंशन की वृद्धि की जाएगी।
- ओबीसी, एससी और एसटी के विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए पूरी स्कॉलरशिप दी जाएगी।
- पिछड़ी बिरादरी के उद्यमियों के लिए हरियाणा सरकार ब्याज मुक्त लोन के रूप में 25 लाख रुपये देने का कार्य करेगी।
- हरियाणा को शिक्षा का ग्लोबल एजुकेशन हब बनाया जाएगा और इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा।
- साउथ हरियाणा में अरावली के जंगलों में 10 हजार एकड़ का इंटरनेशनल लेवल का सफारी बनाया जाएगा, ताकि पर्यटन को आकर्षित किया जा सके।

हाइवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट के क्षेत्र में भी विकास हुआ है जिसके माध्यम से हरियाणा में बड़े परिवर्तन आए हैं। हरियाणा के लिए रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया है। ऑप्टिकल फाइबर से 6 हजार गांवों को जोड़ दिया गया है।

श्री नड्डा ने हरियाणा की जनता से पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने की अपील की।

मुख्य बिंदु

- हरियाणा के जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।
- कांग्रेस की सरकार में हरियाणा की छवि पर्ची-खर्ची, जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार वाले प्रदेश की थी, जबकि मोदीजी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में हरियाणा की छवि नॉन-स्टॉप डेवलपमेंट की बनी है।
- कांग्रेस सरकार में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1.37 लाख रुपए थी, जो आज दोगुनी होकर 3 लाख रुपए तक पहुंच गई है।
- कांग्रेस सरकार में हरियाणा में केवल 8 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती थी, आज 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है।
- हरियाणा में पहले केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज ये संख्या दुगनी होकर 15 हो चुकी है। पहले मेडिकल कॉलेज में केवल 700 सीटें हुआ करती थी, जो अब 2,085 हो चुकी हैं।
- कांग्रेस ने मेनिफेस्टो की प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया है, वे लोगों से छलावा करते हैं। ■

कांग्रेस-एनसी-पीडीपी ने सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया, लेकिन भाजपा सबको जोड़ रही है : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में 19 सितंबर, 2024 को दो जनसभाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले दौर में जम्मू-कश्मीर के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए खुले मन से वोटिंग की है। इससे साफ है कि आर्टिकल-370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू-कश्मीर स्थायी शांति की ओर तेजी से बढ़ चला है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस-एनसी-पीडीपी ने सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया, लेकिन भाजपा सबको जोड़ रही है। आर्टिकल-370 की वापसी के मंसूबे बना रहे कांग्रेस-एनसी-पीडीपी को मोदी डंके की चोट पर कह रहा है कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को कतई लागू नहीं होने दिया जाएगा।

जब देश में वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का फैसला किया, तो शुरुआती वंदे भारत ट्रेनों में से एक, दिल्ली से कटड़ा के लिए चलाई गई। बीते वर्षों में कटड़ा और रियासी रेलवे स्टेशनों पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ है। आज उधमपुर और रामबन की दूरी सिमट गई है। चेनानी-नाशरी टनल बनने से जम्मू और श्रीनगर आने-जाने में समय कम लगता है

श्री मोदी ने कटड़ा में अपने पहले संबोधन के दौरान माता वैष्णो देवी को नमन करते हुए कहा कि ये क्षेत्र हमारी आस्था और संस्कृति की पहचान रहा है। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए इसको कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस और उसके शाही परिवार का कहना है कि हमारे देवी देवता, भगवान ही नहीं हैं। क्या ये हमारे देवताओं का अपमान नहीं है। ऐसा कहने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस के लोग ये सब अनायास नहीं कहते हैं, यह उनकी सोची-समझी चाल है। ये दूसरे धर्मों और देशों से इंपोर्ट की हुई नक्सली सोच है। इसी नक्सली सोच के साथ कांग्रेस ने यहां डोगरा परंपरा पर भी हमला किया है।

कांग्रेस-एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन पार्टियों ने जम्मू-कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। अटलजी की सरकार में जो चिनाब ब्रिज स्वीकृत हुआ था, उसे कांग्रेस-एनसी सरकार ने सालों तक दबाए रखा। अंत में भाजपा ने ही इसे पूरा किया। आज ये शानदार ब्रिज सुविधा के साथ-साथ, दुनियाभर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी कई फीट ऊंचा है। उन्होंने कहा कि जब देश में वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का फैसला किया, तो शुरुआती वंदे भारत ट्रेनों में से एक, दिल्ली से कटड़ा के लिए चलाई गई। बीते वर्षों में कटड़ा और रियासी रेलवे स्टेशनों पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ है। आज उधमपुर और रामबन की दूरी सिमट गई है। चेनानी-नाशरी टनल बनने से जम्मू और श्रीनगर आने-जाने में समय कम लगता है।

राज्य के विकास का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर का पानी, यहां के किसानों के काम आ रहा है। कांग्रेस-एनसी की सरकार तो अपने हक का पानी भी सीमापार जाने दे रही थी। ये यहां कभी बड़े डैम बनाने की हिम्मत नहीं कर पाए। भाजपा सरकार न आती, तो आज भी कठुआ और सांबा जिले के सैकड़ों किसान परिवार बेहाल होते। अब शाहपुर कंडी डैम बनने से हजारों किसानों को नई जिंदगी मिली है। आज जम्मू डिवीजन में 4 बड़े बिजली कारखानों पर काम चल रहा है। इनसे जम्मू वालों को बिजली तो मिलेगी ही, अनेक नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे। आज इस क्षेत्र

में शानदार सड़कें बन रही हैं। रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। इससे टूरिज्म को भी नए पंख लगे हैं। पिछले साल ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू-कश्मीर और 95 लाख श्रद्धालु यहां माता-रानी के दर्शन करने आए। देश का नाम रोशन करने वाले पैरा-एथलीट राकेश और शीतल की सफलता में भी कटड़ा का बड़ा योगदान है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस-एनसी को यहां कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इनके अलायंस की बल्ले-बल्ले हो रही है। इनके घोषणापत्र से पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान के रक्षामंत्री का कहना है कि आर्टिकल-370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है, जो हमारा है। कांग्रेस-एनसी की पोल तो पाकिस्तान ने ही खोल दी है। ये दल यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं, लेकिन मोदी आज कांग्रेस-एनसी को डंके की चोट पर कह रहा है कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 की वापसी नहीं करा सकती। जबसे आर्टिकल-370 की दीवार टूटी है, तब से आतंक और अलगाववाद यहां कमजोर पड़ रहे हैं।

इससे पहले श्री मोदी ने श्रीनगर की पहली रैली में कहा कि जम्मू-कश्मीर में इस वक्त जम्हूरियत का उत्सव चल रहा है। यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग पहली बार दहशतगर्दी के साये के बिना हुई है। अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूटे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को दहशतगर्दी से आजाद कराना, साजिश करने वाली ताकतों को हराना और यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार दिलाना, ये मोदी का इरादा और वादा है। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए हम पूरी ईमानदारी से जुटे हैं। आज पूरे जम्मू-कश्मीर में स्कूल-कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं, बल्कि पेन, किताबें और लैपटॉप हैं। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती, बल्कि यहां नए स्कूल-कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी बनने की खबरें आती हैं। 5 सालों में यहां मेडिकल की करीब 1100, नर्सिंग में 1500 और पैरामेडिकल में 1600 से ज्यादा नई सीटें जुड़ी हैं।

परिवारवादी राजनीति पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की बर्बादी के लिए तीन खानदान जिम्मेदार है। इन्होंने जम्हूरियत और कश्मीरियत दोनों को कुचला है। कांग्रेस-एनसी और पीडीपी के इन तीनों खानदानों को लगता है कि कुर्सी पर कब्जा जमाओ और लोगों को लूटो, ये इनका पैदाइशी हक है, लेकिन अब जम्मू-कश्मीर, इनके शिकंजे में नहीं रहेगा। अब यहां का नौजवान, इनको चैलेंज कर रहा है। जिन युवाओं को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। अब यहां का नौजवान मजबूर नहीं रहा, वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है। मुझे खुशी है कि जम्मू-कश्मीर भाजपा ने भी नौजवानों को रोजगार देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। स्किल डेवलपमेंट के साथ ही बिना धांधली के काबिल लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये सारे काम भाजपा यहां पूरे करके दिखाएगी।

उन्होंने कहा कि एक दौर था, जब लाल चौक आकर तिरंगा

फहराना जान जोखिम में डालने जैसा था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दीवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत को सींचने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन तीन खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। कांग्रेस-एनसी-पीडीपी ने सिर्फ बंटवारा किया और हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। आज दुनिया जम्मू-कश्मीर में बदलते हालात को देखकर खुश है। यहां G-20 का इतना बड़ा इवेंट हुआ। उन्होंने कहा कि यहां भाजपा सरकार बनेगी, तो किसानों के खातों में 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए हर साल जमा होंगे। हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल 18 हजार रुपए जमा करेगी। हर परिवार को 5 लाख की जगह 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा।

श्री मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हम सिर्फ और सिर्फ विकास और तेज तरक्की पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए यहां भाजपा की सरकार जरूरी है।

मुख्य बिंदु

- पहले दौर के चुनाव में भारी मतदान, हम सभी के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात
- अब जम्मू-कश्मीर, इसे बर्बाद करने वाले तीन खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा
- भाजपा, दिल और दिल्ली की दूरी को मिटाने में जुटी है
- कांग्रेस का शाही परिवार; भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता और उसका पोषक है
- दुनिया की कोई ताकत, जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 की वापसी नहीं करा सकती ■

भाजपा सरकार में हरियाणा घोटालामुक्त और विकासयुक्त हो गया: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 सितंबर, 2024 को हरियाणा के रोहतक में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रदेश के विकास की गति को निरंतर बनाए रखने तथा विकास को और गति देने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक का विकास किया और विपक्षी पार्टियों ने यहां विकास को बाधित किया था। इस अवसर पर हरियाण प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश महामंत्री सुश्री अर्चना गुप्ता, प्रत्याशी श्री मनीष ग्रोवर समेत प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि यह प्रदेश जमीन घोटाला के लिए चर्चित होता था। प्रदेश के स्थानीय नुमाइंदा इसमें शामिल होते थे। पिछले दस साल में भाजपा सरकार में किसी को भी पर्ची और खर्ची पर नौकरी नहीं मिली। जिस प्रदेश में पर्ची और खर्ची पर नौकरी मिलती थी, उस प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने पर पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिलने लगीं। जिस प्रदेश में जमीन घोटाले होते थे, भाजपा सरकार में वह प्रदेश घोटालामुक्त और विकासयुक्त हो गया।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में दस साल पहले कोई नेता जनता के सामने अपने काम का रिपोर्ट कार्ड नहीं रखते थे। यहां केवल जाति से जाति को लड़ाना, भाई-भतीजावाद करना, अपनों को लाभ पहुंचाना और परायों को पछाड़ना, पहले इसी तरह की तोड़-फोड़ की राजनीति चलती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति में रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति लाई। प्रधानमंत्रीजी जहां जाते हैं अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जहां जाते हैं, वहां भाजपा सरकार के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले प्रति व्यक्ति आय 1.37 लाख रुपए सालाना थी और आज प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए हो गयी है। लगभग ढाई गुनी हो गयी है। आज से दस साल पहले हरियाणा से 68 हजार करोड़ रुपए का निर्यात होता था और आज हरियाणा 2.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है। दस साल पहले हरियाणा में 7 मेडिकल कॉलेज थे और आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। हरियाणा के हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो गया है। हरियाणा मे 700 एमबीबीएस की सीटें होती थीं और आज 2185 एमबीबीएस की सीटें हैं, तीन गुने से ज्यादा सीटें हो गयी हैं। दस साल पहले 2014 में प्रदेश के 538 गांवों में बिजली मिलती थी और आज 5800 गांवों में 24 घंटें बिजली मिलती है।

श्री नड्डा ने कहा कि दस साल पहले किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति के लिए 1,158 करोड़ रुपए था और भाजपा की सरकार

में किसानों को आज 1,25,00 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। फसल खराब होने पर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हुड्डा जी प्रति एकड़ 6 हजार रुपए देते थे और अब 15 हजार रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है। दस साल पहले बुजुर्गों को एक हजार रुपए पेंशन मिलती थी और आज तीन हजार रुपए मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर हरियाणा में सड़कों की हालत अच्छी हुई, एलीवेटेड रोड बना। फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास रोड बन रहा है। रोहतक में देश का पहला एलीवेटेड रेलवे लाइन बनी। 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश के आधारभूत संरचना के विकसित किया गया है। आज मैं पौने दो घंटे दिल्ली से रोहतक पहुंच गया, जो दस साल पहले संभव नहीं था। दिल्ली-पानीपथ-सोनीपथ क्षेत्रीय रैपिड रेल शुरू हो रहा है। जयपुर, दिल्ली, देहरादून और जम्मू के लिए हिसार एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो गयी है। हरियाणा में एक हजार खेल नर्सरी बनायी गयी है। प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा स्टार्टअप मिशन को आगे बढ़ाया गया है।

मुख्य बिंदु

- हरियाणा में एक ओर कांग्रेस की विनाशकारी सोच है और समाज को तोड़ने की साजिश है तो दूसरी ओर मोदीजी के नेतृत्व में विकास को ही संकल्प मानकर काम करनेवाली भाजपा है।
- जिस प्रदेश में खर्ची और पर्ची पर नौकरी मिलती थी, उस प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने पर मेरिट पर नौकरियां मिलने लगीं।
- कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हुड्डा जी किसानों को केवल 8 फसलों का एमएसपी देते थे और आज भाजपा सरकार प्रदेश में 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है।
- हरियाणा में भाजपा सरकार बनने पर दो लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची सरकारी नौकरी दी जायेगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये दिए जायेंगे। ■

अब जम्मू-कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं, बल्कि टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है: राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 सितम्बर, 2024 को जम्मू एवं कश्मीर के रामबन और बनिहाल की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी एलायंस के घटक दलों ने जम्मू-कश्मीर में लोगों को लंबे समय तक अधिकारों से वंचित रखा। इस बार के विधानसभा चुनावों में पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मिकी समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार को पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार मिला है। वाल्मिकी समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिज़र्व की गई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

श्री सिंह ने कहा कि यह सिर्फ प्रदेश का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता की नजर जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। अमेरिका में इंडियन डायसपोरा के लोगों ने मुझसे पूछा कि जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के चुनाव में क्या होगा? मैंने डंके की चोट पर कह दिया कि जम्मू एवं कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। पहले यहां 6-8 प्रतिशत की पोलिंग हुआ करती थी, लेकिन धारा 370 और 35ए हटने के बाद लोकसभा चुनाव में 58 प्रतिशत पोलिंग हुई। लद्दाख में धारा 370 हटने के बाद 72 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बिना भय और पक्षपात के लोकसभा चुनाव हुए थे, यहां के लोगों ने इसका अनुभव किया है। जम्मू एवं कश्मीर में बदलाव का यह बहुत बड़ा संकेत है।

उन्होंने कहा कि चाहे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हों, चाहे वाल्मिकी समाज के लोग हों, या साफ-सफाई करने वाले लोग हों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में सीट आरक्षित की गयी है। नगरपालिका और नगर पंचायत में भी आदिवासी समाज के लोगों के लिए सीटें आरक्षित की गयी।

उन्होंने कहा कि आजाद भारत की इतिहास में पहली बार जी-20 का एक सम्मेलन कश्मीर घाटी में भी हुआ। यह है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार की खासियत और जम्मू एवं कश्मीर के प्रति उनका विशेष लगाव। मोदी सरकार आने से पहले जम्मू एवं कश्मीर को दुनिया में कहा जाता था कि जम्मू एवं कश्मीर आतंकवाद ग्रसित क्षेत्र है। अब जम्मू एवं कश्मीर के बारे में दुनिया की धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू एवं कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है।

श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस सहित इंडी एलायंस के लोग कहते थे कि धारा 370 हटा दिया गया तो जम्मू एवं कश्मीर में आग लग जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने धारा 370 और 35ए को निरस्त कर दिया, ताकि प्रदेश में खुशहाली आए और प्रदेश का विकास हो सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, उस नेशनल कांफ्रेस ने पार्टी की मेनिफेस्टो में कहा कि उनकी सरकार बनी तो वे धारा 370 को पुनः बहाल करेंगे। लेकिन जम्मू एवं कश्मीर की जनता धारा 370 को पुनः बहाल करना नहीं चाहती है और किसी में हिम्मत नहीं है कि अब धारा 370 को पुनः बहाल कर सके।

प्रमुख बिंदु

- कांग्रेस और इंडी एलायंस के घटक दलों ने जम्मू कश्मीर में लोगों को लंबे समय तक अधिकारों से वंचित रखा। इस बार के विधानसभा चुनावों में पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मिकी समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार को पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार मिल गया है।
- वाल्मिकी समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिज़र्व की गई हैं।
- जो जम्मू-कश्मीर पहले टेररिज्म स्पॉट के तौर पर पूरे देश में जाना जाता था, आज वह टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन चुका है। साढ़े तीन दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया की रैली निकाली गई है।
- नेशनल कांफ्रेस ने पार्टी की मेनिफेस्टो में कहा कि उनकी सरकार बनी तो धारा 370 को पुनः बहाल करेंगे, लेकिन जम्मू एवं कश्मीर की जनता धारा 370 को पुनः बहाल नहीं करना चाहती और किसी में हिम्मत नहीं है कि अब धारा 370 को पुनः बहाल कर सके।
- भाजपा का संकल्प है कि हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और उनके पुनर्वास में तेज़ी लायेंगे। इसी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, पीओजेके के शरणार्थियों और वाल्मीकि और गोरखा समाज के लोगों के पुनर्वास में भी तेज़ी लायेंगे। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप दिया: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 21 सितंबर, 2024 को जम्मू एवं कश्मीर के मेंढर, सुरनकोट, थानमंडी, रजौरी एवं अखनूर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित विशाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और जम्मू-कश्मीर की जनता से राज्य में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया।

श्री शाह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर का विधानसभा चुनाव तीन परिवारों— अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू-गांधी परिवार के परिवारवादी शासन को समाप्त करने वाला है। इन तीनों परिवार ने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को रोककर रखा था। अगर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार नहीं आती तो क्या जम्मू एवं कश्मीर में पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनाव होते?

उन्होंने कहा कि 90 के दशक से लेकर जम्मू एवं कश्मीर में इन लोगों ने दहशतगर्दी फैलाई। 40 हजार से ज्यादा लोग मारे गए। ये तीनों परिवार दहशतगर्दी को नहीं रोक पाए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी को समाप्त किया और युवाओं के हाथों में पत्थर की जगह लैपटॉप दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आने के बाद ओबीसी, दलित, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को आरक्षण मिला। सबसे बड़ी बात यह कि पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण का लाभ मिला।

अखनूर की जनसभा में राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए श्री शाह ने कहा कि मैं राहुल बाबा से कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में वोट चाहिए तो देश की जनता साफ़ करें कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी, नेशनल कांफ्रेंस के एजेंडे से सहमत हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के एजेंडे से सहमत है। पाकिस्तान और राहुल गांधी, पाकिस्तान और नेशनल कांफ्रेंस का एजेंडा एक समान है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि उनकी बात का समर्थन पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कर रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि धारा 370 हटी तो कोई यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। महबूबाजी, धारा 370 हट गया, चुनाव हो रहा है और लाल चौक पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। इन्होंने अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. अम्बेडकर के सम्मान में पंच तीर्थ का निर्माण किया। ■

'भाजपा सरकार सभी अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देगी'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 17 सितंबर, 2024 को हरियाणा के लोहारु और फरीदाबाद में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया और सेना, किसान व अग्निवीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस द्वारा राजनीति करके हरियाणा के लोगों को भ्रमित करने की जमकर आलोचना की। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली, हरियाणा चुनाव सह-प्रभारी श्री बिप्लब कुमार देब, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री कुलदीप बिश्नोई, राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री शाह ने कहा कि हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला प्रदेश है और यही सैनिक 40 वर्षों से 'वन रैंक, वन पेंशन' की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। हरियाणा की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी को वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने 2015 में 'वन रैंक, वन पेंशन' को लागू कर दिया। जब केन्द्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई है, तो कांग्रेस और राहुल गांधी इस पर राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा एंड कंपनी पूछ रही है कि अग्निवीरों का बाद में क्या होगा? भारत सरकार के गृह विभाग ने अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है। हरियाणा के जितने भी अग्निवीर हैं श्री नायब सिंह सैनी उन्हें हरियाणा सरकार में ही नौकरी दे देंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों और खिलाड़ियों की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में हरियाणा के प्रत्येक जिले में खेल के लिए बेहतर मैदानों का निर्माण कराया और युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया है। कांग्रेस राज में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी कम शासन नहीं किया है उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एमएसपी पर कितनी खरीद की है, हुड्डा जी ने एमएसपी के नाम पर केवल 4 फसलों की ही खरीदारी की, जबकि श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 फसलों की खरीदारी एमएसपी पर करती है। 10 वर्षों में पूरे देशभर में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदारी भाजपा शासित हरियाणा राज्य में हुई है।

श्री शाह ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आशीर्वाद दिया है, 2014 में 4 की जगह 47 सीटें दीं, 2019 में सरकार बनाई, 2024 में भी भाजपा को आशीर्वाद देकर सरकार बनाएं। ■

प्रधानमंत्री मोदीजी ने देश के संकल्पों को सिद्धि में बदला है : जगत प्रकाश नड्डा

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर 17 सितंबर, 2024 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम के तहत ब्लड डोनेशन कैंप एवं प्रधानमंत्रीजी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय कार्यालय प्रभारी श्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, भाजपा राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख एवं सांसद श्री अनिल बलूनी एवं सह प्रमुख डॉ. संजय मयूख सहित कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा दिवस के रूप में मनाती है तथा उनके जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती तक भाजपा कार्यकर्ता 'सेवा पखवाड़ा' मनाते हैं। इस दौरान देश भर में भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान देते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, झुग्गी बस्तियों में सेवा अभियान चलाते हैं तथा सेवा के कई अन्य कार्य किये जाते हैं।

इस अवसर पर श्री नड्डा ने उपस्थित मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्म दिवस है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और उनके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक हर साल 'सेवा पखवाड़ा' मनाती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समर्पण के साथ देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, युवा, महिला और किसान की चिंता की और उनके जीवन स्तर उपर उठाने के लिए निरंतर काम किया है। प्रधानमंत्रीजी ने देश के संकल्पों को सिद्धि में बदला है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ऐसे महान शख्सियत के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप मे मनाते हैं। ये मेरी कामना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इसी तरह देश की सेवा के साथ मानवता की सेवा में लगे रहें और हम लोग उनके सेवा कार्यों में योगदान देकर उन्हें ताकत दें।

श्री नड्डा ने कहा कि आज विश्वकर्मा पूजा दिवस भी है और आज

ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन भी पूरे हुए हैं। इसलिए यह दिन बड़ा विशेष है। भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के दौरान रक्तदान, वृक्षारोपण, झुग्गियों बस्तियों की सफाई, स्वच्छता अभियान समेत सेवा भाव से कई तरह के अभियान चला रही है। मोदी 3.0 अर्थात् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में तीव्र गति से काम हुए है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में अगले चार-पांच दिनों तक मोदी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सौ दिनों की उपलब्धियों को मंत्रियों द्वारा जनता को बताया जाएगा। साथ ही, भारतीय जनता पार्टी मोदी 3.0 अर्थात् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0 में सौ दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान बनाने की मंजूरी दी गयी। मंजूरी के साथ ही पक्के मकान बनाने का काम भी शुरू हो गया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में अब तक लगभग दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पहुंच गयी है। सौ दिनों में मोदी सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि बढ़ा दी गयी है। इस दौरान 15 नए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गए हैं। 8 नेशनल हाईस्पीड रोड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गयी है। 8 नए ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की मंजूरी दी गयी है। 12 नए स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी गयी है। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गयी है।

श्री नड्डा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों से जुड़ी योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत अब देश के 70 साल से उपर के लोगों के लिए साल में पांच लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, चाहे वह व्यक्ति किसी भी आमदनी और किसी भी सामाजिक वर्ग से संबंध रखता हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण की मंजूरी दे दी गयी है। इसके तहत 25 हजार गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए लगभग 62,500 किलोमीटर ऑलवेदर ग्रामीण सड़कों को निर्माण होगा। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में ऐसे अनेक काम हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यों का जिक्र मैंने किया है। ये सभी कार्य केवल 100 दिनों में हुए हैं। देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' का संकल्प लेकर चल पड़ा है।

मुख्य बिंदु

- भाजपा हर बार की तरह इस बार भी 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक 'सेवा पखवाड़ा' मना रही है जिसके दौरान रक्तदान, वृक्षारोपण, झुग्गी बस्तियों की सफाई, स्वच्छता अभियान समेत कई तरह के सेवा कार्य

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 17 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 17 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 17 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का दौरा करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

'स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता'

स्वच्छ राष्ट्र के लिए 15 दिवसीय राष्ट्रीय सामाजिक एकजुटता अभियान का शुभारंभ

वर्ष 2017 से शुरू हुआ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान हर साल 'स्वच्छ भारत दिवस' आगमन से पहले आयोजित किया जाता है, जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) यह अभियान पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त रूप से चला रहा है। 'स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता' (4S) की थीम पर आधारित यह अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर, 2024 को समाप्त होगा।

स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता (4S) 2024 को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित रखा गया है। इसमें (i) स्वच्छता की भागीदारी – जन भागीदारी, स्वच्छ भारत के लिए जागरूकता और बढ़ावा देने वाली गतिविधियां (ii) संपूर्ण स्वच्छता – व्यापक स्वच्छता अभियान और स्वच्छता लक्षित इकाइयों जैसे चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों का समयबद्ध परिवर्तन और (iii) सफाई मित्र सुरक्षा शिविर – सिंगल विंडो सेवा, सफाई कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य जांच के लिए सुरक्षा और सम्मान शिविर शामिल हैं।

अभियान में 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसमें नागरिकों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, विकास संगठनों, कॉर्पोरेटर्स, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत, जिलों आदि से भी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गई है। 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण के अंतर्गत अभियान सरकार के सभी अंगों– राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रालयों, शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों की क्षेत्रीय इकाइयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शामिल होने की उम्मीद है।

तैयारियों से संबंधित गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता (4S) 2024 अभियान के लिए चल रही तैयारियों का आकलन और समीक्षा करने के लिए MoHUA और DDWS के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। व्यापक सार्वजनिक अभियान का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुव्यवस्थित करने के लिए MoHUA और DDWS के सचिवों ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी, उद्योग एवं विकास भागीदार और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बैठक की। तैयारियों के स्तर का आकलन करने और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ अतिरिक्त समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ■

किये जा रहे हैं।

- देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत' का संकल्प लेकर चल पड़ा है। उन्होंने देश के संकल्पों को सिद्धि में बदला है। हम उनके उद्देश्यपूर्ण जीवन से कई महत्वपूर्ण चीजें सीख सकते हैं।
- मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों में कई क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गयी और 25 हजार गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए लगभग 62,500 किमी ऑलवेदर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी शुरू हुआ।
- मोदी सरकार 3.0 में सौ दिन के अंदर ही पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान बनाने की मंजूरी दी गयी। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी की गई है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी बढ़ाई गई है।
- इन्हीं 100 दिनों में मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी है। इस दौरान 15 नए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो गए हैं। साथ ही 8 नेशनल हाईस्पीड रोड कॉरिडोर, 8 नए ब्रॉडगेज रेलवे लाइन और 12 नए स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी दी गयी है।
- समाज के सभी वर्गों से जुड़ी योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत अब देश के 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए साल में पांच लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। ■

गरीब कल्याण, सुरक्षा और गौरव के 100 दिन

प्रथम 100 दिनों में ही शुरू की गईं लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार ने 17 सितंबर, 2024 को अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। सरकार ने 100 दिनों के अति अल्प समय में ही न केवल गरीब कल्याण, सुरक्षा और देश के गौरव हेतु कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, बल्कि अनेक कल्याणकारी पहल व परियोजनाएं भी शुरू कीं। इन प्रमुख उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है:

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

- 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी, प्रमुख फोकस सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग।
- महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपये से वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 (PMGSY-IV) के तहत 49,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से 25 हज़ार अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/अपग्रेडेशन मंजूर।
- 50,600 करोड़ रुपये की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देना स्वीकृत।
- 936 किलोमीटर में फैले 08 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी।
- लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई।

8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी

- रेल यात्रा को तेज़ और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी, जिससे 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे।
- वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी।
- पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज की मंजूरी।
- अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाए जाएंगे।
- बैंगलोर मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित।
- अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित।
- 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए MSP बढ़ाया गया, जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ (12 करोड़ किसान लाभान्वित)।
- 12,100 करोड़ रुपये से आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी।
- 14,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 07 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी, जिनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शामिल, जिससे कृषि क्षेत्र में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।

- राष्ट्र स्तरीय समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है; मसौदा नीति भी तैयार कर ली गई है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) व जैविक उत्पाद परिषद् (उत्तराखंड) के बीच MoU, NCOL द्वारा उत्तराखंड के किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा। लाभ का उचित हिस्सा सीधे किसानों के खाते में।
- मक्के से भी एथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण।

प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा

- प्याज और बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से 20% करने का निर्णय।
- कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में ड्यूटी को 12.5% से 32.5% बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर ड्यूटी को 13.75% से 35.75% करने का निर्णय।
- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार।
- जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ रुपये से कई कृषि योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं शुरू।
- वाराणसी की पहली यात्रा के दौरान मोदी जी के द्वारा स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को कृषि में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।
- मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के मिशन मौसम को मंजूरी।
- **एग्रीस्योर नामक एक नया फंड लॉन्च:** कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने तथा स्टार्ट-अप और रूरल इंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए शुरू।

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

- **टैक्स राहत:** 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- वेतन पाने वाले कर्मचारी 17,500 रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया।
- पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया।
- इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में व्यापक समीक्षा।

सरकारी कर्मचारियों को सरकार की सौगात

- **यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू:** 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

- **वन रैंक, वन पेंशन (OROP):** सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत।
- शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर।
- ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण की स्वीकृत।
- (2014 से अभी तक कुल (शहरी+ग्रामीण) 4 करोड़ 27 लाख घर)।
- **पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** जून से अगस्त, 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया।
- पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा, 3,400 करोड़ रुपये की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस

- स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे Angel Tax को समाप्त किया गया।
- विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया।
- भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फण्ड बनाया जाएगा।
- **GENESIS प्रोग्राम:** Tier-II और Tier-III शहरों में स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (GENESIS) प्रोग्राम को मंजूरी दी गई।
- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा, जो निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को बेहतर बनाएंगे।
- मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये

की गई, जिससे पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा।

- MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई, जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा और उनके लिए मशीनरी और अन्य सामान की खरीद आसान होगी।
- MSMEs और परंपरागत कारिगरों के लिए PPP मोड से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स तैयार किए जाएंगे, जो निर्यात सेवाएं प्रदान करेंगे और वैश्विक बाजार में इजी एक्सेस देगा।

रोजगार सृजन पर जोर: 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा

- 2 लाख करोड़ रुपये के पीएम पैकेज की घोषणा, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा।
- लक्ष्य: 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना।
- 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, allowances और एकमुश्त सहायता राशि।
- केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नए नियुक्तियों की घोषणा की।
- 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा।
- पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
- 1 लाख रुपये तक की आय वाले कर्मचारियों को EPFO में सरकारी योगदान का फायदा।
- Employers को हर 1 लाख रुपये तक की आय वाले नए कर्मचारियों को जोड़ने पर 2 साल तक 3,000 रुपये प्रतिमाह का reimbursement।
- ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण, 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से नई उद्योगों को बढ़ावा और रोजगार सृजन।
- पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने से रोजगार सृजन।
- स्टार्ट-अप्स और MSME के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन।
- Khelo India Rising Talent Identification (KIRTI) योजना की शुरुआत।

सशक्त नारी शक्ति: 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह

- दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) के तहत: 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाए गए।
- **लखपति दीदी योजना:** श्री मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए।
- 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक की कमाई कर रही हैं।
- पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से SHGs और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा।
- 2,500 करोड़ रुपये का Community Investment Fund जारी, 4.3 लाख SHGs के 48 लाख सदस्यों को लाभ।
- 5,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण जारी, 2 लाख 35 हजार 400 SHGs के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ।

ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तीकरण

- **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान:** 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- **NAMASTE योजना का विस्तार:** सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण होगा।
- **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र:** अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए, जिनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं।
- **PM SURAJ का विस्तार:** अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मचारियों के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय:** 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ।
- नए विद्यालय और स्मार्ट कक्षाएं: 40 नए विद्यालय बनाए गए और 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं।
- **वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024:** वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन

और संरक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी।

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा, जिससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को लाभ होगा।
- 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं, जिससे हेल्थकेयर सिस्टम को प्रभावी बनाने और मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
- नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए U-WIN पोर्टल शुरू किया गया।
- देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रहा है।
- महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदायों में सिकल सेल डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
- कैंसर से पीड़ित लोगों के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट।
- PM E-DRIVE योजनाः 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- डिजिटल हेल्थकेयरः आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) पर 'स्कैन और शेयर' सुविधा, जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट-पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई।

भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश

- भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना, स्वदेशी सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना।
- **सेमीकंडक्टरः** गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना। 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित, प्रतिदिन 60 लाख चिप्स की उत्पादन क्षमता।

- अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए 1000 करोड़ रुपये की वेंचर कैपिटल फंड योजना।
- 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया (चंद्रयान व मंगलयान की सफलता पर)।
- आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल।
- 16 अगस्त को SSLV-D3 पर EOS-08 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण।
- **50 हज़ार करोड़ रुपये से राष्ट्रीय अनुसंधान कोष,** 10,500 करोड़ रुपये से 'विज्ञान धारा' योजना।

3 नए कानून लागू

- औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई, 2024 को 3 नए कानून लागू।
- **भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियमः** संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं फॉरेंसिक को बढ़ावा तथा Digitalization से कानून व्यवस्था सुदृढ़।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्टब्लेयर के नाम परिवर्तन कर श्री विजयपुरम की गई।
- प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए 'National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme' की मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2,250 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय।
- **पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024।**
- लोक शिकायत निवारण के लिए CPGRAMS दिशा-निर्देश जारी किए गए।

पूर्वोदय योजना

- पूर्वोदय योजनाः बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए योजना।
- शहरी बाढ़ प्रबंधन, ग्लेशियल Lake Outburst Flood Risk Mitigation के लिए 6,350 करोड़ रुपये की परियोजनाएं।
- लद्दाख में 5 नए जिले (ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग), कुल जिलेः 7 (लेह और कारगिल सहित)।
- **25 जून को 'संविधान हत्या दिवस।**

ऊर्जा सुरक्षा

- पूर्वोत्तर में 4,100 करोड़ रुपये की हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी।
- राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच Joint venture सहयोग।

- VGF (Viability Gap Funding) योजना के तहत 12,400 करोड़ रुपये से अधिक के हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी।
- 7450 करोड़ रुपये की ऑफ-शोर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत।
- **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन:** इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए second tranche प्रदान की गई, इससे घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफेक्चरिंग capacity प्रति वर्ष 1.5 गीगावाट होगी।
- PSU को वृक्षारोपण व पर्यावरण बहाली के लिए Green Credit Programme की शुरुआत। इसी दिशा में Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase-III (FAME-III) योजना।
- **जी-वन योजना:** उन्नत जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी-वन योजना।

विदेश नीति

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की रूस व यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्रा।
- श्री मोदी की रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राएं, इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी।
- रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी को 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द् एपोस्टल' सम्मान।
- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ फिजी' और तिमोर लेस्टे के 'ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे' से सम्मानित किया गया।
- सिंगापुर और किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार ब्रुनेई दारुस्सलाम की यात्रा।
- किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 41 वर्षों के बाद यात्रा ऑस्ट्रिया और 45 वर्षों के बाद पोलैंड यात्रा।
- भारत ने 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
- पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई।

आपदा प्रबंधन

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन हेतु आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किया गया।
- अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाओं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटीगेशन हेतु राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये स्वीकृत। ('नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड',' नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड', 'स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड' और 'स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड' के तहत)।
- आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ERSS 2.0) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू।
- आंध्र प्रदेश की बाढ़ के लिए एक एक्सपर्ट टीम का गठन।

सुरक्षा: NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता

- 4 सितंबर को 35 सालों के संघर्ष समाप्त करते हुए NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता किया गया। इसके तहत 328 सशस्त्र कैडर हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।
- मानस (MANAS) हेल्पलाइन का शुभारंभ।
- साइबर अपराध से निपटने वाले सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए 'समन्वय' प्लेटफॉर्म शुरू किया गया।
- अगले 5 साल में 5 हजार साइबर कमांडों तैयार किए जाएंगे।
- साइबर अपराध की सूचना देने के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
- बैंकों और वित्तीय इन्टरमीडियरीज के साथ मिलकर I4C में अत्याधुनिक 'साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र' (CFMC) की स्थापना की गई।
- सस्पेक्ट रजिस्ट्री: मोबाइल नंबर, यूआरएल/वेबसाइट, आईएमईआई और अन्य पहचानकर्ताओं का एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाया गया है। ■

एकात्म मानववाद: समाज के सर्वांगीण विकास की कुंजी

डॉ. सुभाष सरकार

इस वर्ष 'एकात्म मानववाद' के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 4 जून, 1964 को प्रस्तुत किया था। यह परिवर्तनकारी विचारधारा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है, जो व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक समृद्धि के बीच महत्वपूर्ण संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह भारत के प्राचीन दर्शन, एक समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा का पोषण करती है, जबकि कई पश्चिमी विचारधाराएं भौतिक सफलता को प्राथमिकता देती हैं।

दीनदयाल जी ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सामाजिक विकास की तुलना उचित पोषण से की, जो जीवन के सभी पहलुओं के आपसी संबंध को उजागर करती है। यह एक अंतर्दृष्टि है जिसे आधुनिक विज्ञान अब मान्यता देता है।

एकात्म मानववाद, जो एकता, सांस्कृतिक अखंडता और समग्र कल्याण जैसे मूल मूल्यों में दृढ़ता से निहित है, भारत को समावेशी और सतत विकास की ओर मार्गदर्शित करता है। यह विचारधारा व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है, एक सांस्कृतिक रूप से विविध राष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक विभाजन को पाटने की मार्गदर्शक शक्ति बनती है।

दीनदयाल जी ने समाज को एक जीवित जीव के रूप में कल्पित किया, जो उपजाऊ मिट्टी में पनपने वाले वृक्ष के समान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज की वृद्धि और जीवन-शक्ति, भूमि और उसके लोगों के साथ के पोषण संबंध पर निर्भर करती है। यह संबंध मानव और उनके पर्यावरण के बीच सामंजस्य पर जोर देता है और यह सुझाव देता है कि सच्चा विकास केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि समाज के सभी स्तरों की भलाई से उत्पन्न होता है, जिसे प्रकृति, संस्कृति और समुदाय के संबंधों द्वारा बनाए रखा जाता है।

5 जून, 1964 को दीनदयाल जी ने 'व्यक्ति और समाज' शीर्षक से एक परिवर्तनकारी व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने व्यक्ति और सामूहिकता के बीच के संबंध की गहरी समझ व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यक्ति और समाज दोनों आवश्यक तत्वों से मिलकर बनते हैं— शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। यह समग्र दृष्टिकोण मानव अस्तित्व के बहुआयामी स्वभाव को पहचानने और इसके व्यापक सामाजिक ढांचे के साथ संप्रेषित करने की महत्ता को उजागर करता है।

अपने समाज की खोज में दीनदयाल जी ने तर्क किया कि एक समृद्ध समुदाय अंतर संबंधित घटकों पर आधारित होता है, जिसमें लोग, सामूहिक इच्छा या संकल्प, शासन प्रणालियां और प्रचलित संस्कृति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये तत्त्व एक साथ मिलकर एक जीवंत और स्थायी समाज बनाते हैं।

उनका दृष्टिकोण सैद्धांतिक ढांचों से परे था। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सबसे गरीब व्यक्तियों को दान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के रूप में नहीं रखा गया। इसके बजाय, उन्होंने अन्त्योदय जैसे संरचित पहलों का समर्थन किया, जो आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाते हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करके ये पहल हाशिए पर रहने वाले लोगों को समाज में सार्थक योगदान देने और गरीबी के चक्र को तोड़ने में सक्षम बनाती हैं।

दीनदयाल जी का दृष्टिकोण एक ऐसे समाज के निर्माण पर जोर देता है जो गरिमा, सशक्तीकरण और सतत विकास को महत्व देता है। एकात्म मानववाद की पहचान की गई प्रमुख समाजिक आवश्यकताओं में नवजात देखभाल, उचित आवास, स्वास्थ्य सुरक्षा, और आजीविका के लिए शिक्षा और कौशल विकास शामिल हैं।

दीनदयाल जी ने बल दिया कि समाज पर सदस्यों की देखभाल करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो एकात्म मानववाद के केंद्र में स्थित सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को दर्शाता है। ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं, जो भारत को समावेशी विकास की ओर मार्गदर्शित करता हैं और सभी नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

दीनदयाल जी ने पूंजीवाद और साम्यवाद जैसी विचारधाराओं की भी जांच की, इन्हें संघर्ष से प्रभावित सीमित दृष्टिकोणों के उत्पाद के रूप में देखा। उन्होंने बल दिया कि विश्व स्तर पर भिन्न विचारधाराओं के बीच संघर्ष को भारत की एकीकृत सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो विविध दृष्टिकोणों के बीच समझ और एकता

एकात्म मानववाद, जो एकता, सांस्कृतिक अखंडता और समग्र कल्याण जैसे मूल मूल्यों में दृढ़ता से निहित है, भारत को समावेशी और सतत विकास की ओर मार्गदर्शित करता है। यह विचारधारा व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है, एक सांस्कृतिक रूप से विविध राष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक विभाजन को पाटने की मार्गदर्शक शक्ति बनती है

को बढ़ावा देती है।

आर्थिक दृष्टिकोण से दीनदयाल जी ने संसाधनों की प्रचुरता को पहचानने पर जोर दिया, न कि कमी पर और कहा कि वित्तीय प्रभाव को मानव संबंधों पर हावी नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक आदर्श समाज में दंड के लिए मध्यम दृष्टिकोण का समर्थन किया, जो एकीकृत जीवन के लक्षण है, जो उनके दया और आपसी संबंध वाले समुदाय के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

25 अप्रैल, 1965 को, एकात्म मानववाद दर्शन की 'युगानुकूल अर्थ-रचना' से प्रेरित होकर, उन्होंने एक आर्थिक ढांचा प्रस्तावित किया जो सतत और मानवीय संसाधन उपयोग को प्राथमिकता देता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के आर्थिक स्वामित्व कि पहचान की जैसे निजी उद्यम, सार्वजनिक कंपनियां, सहकारी समितियां, और छोटे व्यवसाय और इनके संभावित योगदानों को सामाजिक कल्याण में उजागर किया।

पूंजीवाद प्रबंधन और धन पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि साम्यवाद श्रम पर जोर देता है। दीनदयाल जी ने सफल उद्योगों के लिए आवश्यक '7 M's' का परिचय दिया— लोग (Men), सामग्री (Material), मोटरपॉवर (Motor Power), मशीन (Machine), विपणन (Marketing), धन (Money) और प्रबंधन (Management)। एकात्म मानववाद इन तत्त्वों को एकीकृत करता है ताकि सभी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले।

दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद के अंतर्गत छह आर्थिक सिद्धांतों का उल्लेख किया, जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

1. **न्यूनतम आवश्यकताएं और आश्वासन:** यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हों।
2. **न्यूनतम से परे समृद्धि:** सामूहिक प्रयासों के माध्यम से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय समृद्धि को बढ़ाना।
3. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और स्वयंसेवा:** वरिष्ठ पेशेवरों को स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने और सामाजिक योगदान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. **उत्पादकों के लिए अनुकूल तकनीक:** उत्पादकों के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से लाभकारी तकनीक को सुविधाजनक बनाना।
5. **सांस्कृतिक संरक्षण:** राज्य की सांस्कृतिक जीवन और मूल्यों को संरक्षित करना।
6. **उद्यम स्वामित्व का समन्वय:** सरकारी और सामाजिक सहयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्यम स्वामित्व को समन्वयित करना।

पूंजीवाद प्रबंधन और धन पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि साम्यवाद श्रम पर जोर देता है। दीनदयाल जी ने सफल उद्योगों के लिए आवश्यक '7 M's' का परिचय दिया— लोग (Men), सामग्री (Material), मोटरपॉवर (Motor Power), मशीन (Machine), विपणन (Marketing), धन (Money) और प्रबंधन (Management)। एकात्म मानववाद इन तत्त्वों को एकीकृत करता है ताकि सभी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण के अनुसार नरेन्द्र मोदी सरकार ने अंत्योदय के मार्ग को अपनाया है, जिसे 'सब का साथ, सबका विकास' के विचार में समाहित किया गया है। यह दृष्टिकोण समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र के विकास यात्रा में कोई पीछे न रहे।

स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, ये व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं; उनके कौशल को बढ़ाते हैं और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। स्किल इंडिया कार्यबल को तेजी से बदलते नौकरी बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक क्षमताओं से लैस करता है, नवाचार और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। वहीं, मेक इन इंडिया स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित करता है और वैश्विक व्यवसायों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं और देशभर में आर्थिक गतिविधि बढ़ती है।

ये पहलें 21वीं सदी में भारत की विशाल

संभावनाओं एवं दृढ़ संकल्पना को दर्शाती हैं। कौशल विकास और उद्यमिता को प्राथमिकता देकर, सरकार एक उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जहां हर नागरिक राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सके और लाभान्वित हो सके।

जब भारत वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, यह समग्र दृष्टिकोण न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज के ताने-बाने को भी मजबूत करता है, एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है।

सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कई योजनाएं लॉन्च की हैं, जो हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए उनके दृष्टिकोण के साथ मेल खाती हैं। कार्यक्रम जैसेः

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना (PDDUUKSY)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (PDUNWFS)

ये पहलें विशेष रूप से युवा और महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए गांवों के विकास और गरीबों, किसानों और हाशिए पर रह रहे समुदायों के लाभ को बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन की गई हैं। इन समूहों को प्राथमिकता देकर, सरकार एक अधिक समान समाज बनाने का लक्ष्य रखती है, जहां हर किसी को फलने-फूलने का अवसर मिले।

मुद्रा, जन-धन, उज्ज्वला, और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम देश भर में जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुद्रा छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, विशेषकर महिलाओं के लिए। जन-धन योजना ने वित्तीय समावेशन में क्रांति लाई है, लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है और बचत को बढ़ावा दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

उज्ज्वला ने परिवारों के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की सुनिश्चितता प्रदान करके जीवन को बदल दिया है, पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया है। इसी तरह, स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे साफ-सुथरे रहने के वातावरण और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों की प्राप्ति हुई है।

मुद्रा, जन-धन, उज्जवला, और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रम देश भर में जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुद्रा छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, विशेषकर महिलाओं के लिए। जन-धन योजना ने वित्तीय समावेशन में क्रांति लाई है, लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है और बचत को बढ़ावा दिया है

2024 में इन पहलों ने भारत में जीवन-यापन की सुविधा को महत्वपूर्ण रूप से सुधार दिया है, जिससे दैनिक जीवन अधिक आरामदायक और सुरक्षित बन गया है। सस्ते आवास और आवश्यक चिकित्सा उपचार तक बेहतर पहुंच के साथ नागरिक स्वस्थ, अधिक उत्पादक जीवन जी सकते हैं। इन कार्यक्रमों का सामूहिक प्रभाव न केवल व्यक्तिगत भलाई को बढ़ावा देता है, बल्कि सामुदायिकता की भावना को भी मजबूत करता है, जिससे सभी के लिए उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।

जैसे ही भारत, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिगत नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, नागरिकों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करता है कि हर कोई राष्ट्र की विकास कथा में भाग ले सके। उनके निरंतर प्रयास एक बेहतर भारत बनाने के लिए उस विश्वास को मजबूत करते हैं जिससे सभी के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध जीवन संभव है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों के माध्यम से पीएम मोदी एक ऐसा भविष्य बनाने की नींव रख रहे हैं, जहां हर नागरिक फल-फूल सके।

जैसे-जैसे भारत व्यापक विकास की ओर बढ़ता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का सिद्धांत समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बना हुआ है। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक प्रगति से परे समाज के सभी क्षेत्रों को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखता है, साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करता है। अन्त्योदय यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय पीछे न रह जाएं।

जैसे आजकल हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लगभग 100 दिन पूर्ण होने का जश्न मना रहे हैं, ऐसे में एकात्म मानववाद के सिद्धांत नीतियों को प्राथमिक रूप से मानव कल्याण हेतु समझना चाहिए। अन्त्योदय पर ध्यान केंद्रित करके हम उन लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं जो हाशिए पर रह रहे लोगों को उठाने के लिए भारत की आवश्यकताओं को दर्शाते हैं।

इन विचारों को नीति निर्माण में एकीकृत करना सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यह हमें एक अधिक समान समाज की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता न केवल दीनदयाल जी की विरासत को सम्मानित करती है, बल्कि समृद्ध और एकजुट भारत की मजबूत नींव रखती है, जहां हर व्यक्ति को फलने-फूलने का अवसर मिलता है। ■

(लेखक भारत सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री हैं)

मोदी स्टोरी

जब नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका में अपना बैग खो दिया

—हीरूभाई पटेल, एनआरआई-यूएसए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तीन दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर थे। वैसे तो श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में कई बार अमेरिका की यात्रा की है, लेकिन उन्होंने 1990 के दशक में एक साधारण भाजपा नेता के रूप में भी अमेरिका की दो यात्राएं की थीं।

1997 में एक बार ऐसी ही यात्रा के दौरान उनका बैग खो गया। इस घटना से अमेरिका में उनके मेजबानों को उनके शांत स्वभाव एवं ईमानदारी का परिचय मिला।

वह विश्व हिंदू परिषद् के एक कार्यक्रम में अतिथि थे। कार्यक्रम के बाद जब वह अपने मेजबान के घर पहुंचे, तो वह कार से अपना बैग निकालने लगे, लेकिन उन्होंने पाया कि वह गायब था। ऐसा लग रहा था कि बैग चोरी हो गया था, बैग में उनका पासपोर्ट, पैसे और यहां तक कि उनके कपड़े भी थे।

श्री मोदी के धैर्य को याद करते हुए इस घटना के दौरान उनके साथ वहां मौजूद एनआरआई श्री हीरूभाई पटेल कहते हैं, "तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद श्री नरेन्द्र मोदी शांत रहे और सभी को चिंता न करने के लिए आश्वस्त किया, जिससे दबाव में भी धैर्य बनाए रखने की उनकी क्षमता सभी के समक्ष आयी।"

श्री मोदी ने अगले पांच दिन अपने मेजबान के घर पर बिताए तथा धैर्यपूर्वक पासपोर्ट की प्रतीक्षा की।

अमेरिका से प्रस्थान से पहले उन्होंने विनम्रतापूर्वक खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ डॉलर उधार मांगे, क्योंकि उनके पैसे भी चोरी हो गए थे। श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मेजबानों को आश्वासन दिया कि वह भारत जाकर, उनके रिश्तेदारों को यह राशि वापस कर देंगे, इस वादे को उन्होंने अगले कुछ दिनों में ही तुरंत पूरा कर दिया। यह दर्शाता है कि श्री मोदी संकट की स्थिति को किस धैर्य के साथ निपटते हैं। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

श्री गोविंदराजू वेंकट लक्ष्मीनरसिम्हा राव

जन्म: 24 फरवरी, 1926
सक्रिय वर्ष: 1952-1980
जिला: गुंटूर , आंध्र प्रदेश

श्री गोविंदराजू वेंकट लक्ष्मीनरसिम्हा राव 'जी.वी.एल. नरसिम्हा राव' के नाम से प्रसिद्ध थे। वह बहुत कम उम्र में ही गुंटूर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में आयोजित होने वाले जम्मू और कश्मीर सत्याग्रह में भाग लेने वाली आंध्र प्रदेश की टीम का नेतृत्व किया था। बांग्लादेश मुक्ति सत्याग्रह में भी उनकी अहम भूमिका रही। श्री जी.वी.एल. राव जी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जनसंघ के विस्तार के लिए प्रदेशभर में कार्य किया। वह जनसंघ के शुरुआती दिनों से ही पार्टी से जुड़ गये थे। पार्टी की पत्रिका जनसंदेश के प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण वर्गों की आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने व्यवस्था बनाने और पूरे राज्य में विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 'रुपये का अवमूल्यन', पार्टी की विदेश नीति, सहकारी आंदोलन के खिलाफ, राज्य परिषद् में जुपुडी तथा जम्मू और कश्मीर मुद्दे जैसे विभिन्न विषयों पर किताबों का लेखन भी किया। ■

सरकार के 100 दिन

विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम

अरुण सिंह

मोदी जी ने सुशासन से सरकारों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु नए आदर्श गढ़े हैं, यह देश ने बीते दो कार्यकालों में देखा है कि कैसे सरकार बनते ही मिशन मोड में कार्य प्रारंभ हो जाता है। मोदी जी की दूरदर्शिता से ही देश के नागरिक पहली बार एक ही शासनकाल में भूमिपूजन और उद्घाटन दोनों कार्यक्रम देखते हैं। पहले यह संभव नहीं था, मोदी जी अपने ही कीर्तिमान बनाकर उन्हें तोड़ पुनः नए कीर्तिमान बनाते हैं और यह हम लगातार तीसरे कार्यकाल में देख रहे हैं। मोदी जी ने शासन और लाभार्थी के बीच 85/15 के कांग्रेसी अनुपात को DBT द्वारा शत-प्रतिशत कर दिया है, यह सुशासन और शुचिता का उज्ज्वल उदाहरण है, यह मोदी जी जैसा कोई त्यागमय जीवन जीने वाला व्यक्ति ही कर सकता है।

चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को काम दिया था कि जितने भी विकास कार्य पाइपलाइन में हैं, उन्हें जो भी नई सरकार आएगी, उसके लिए पूरा करके रखना है, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। मोदी जी के सोच का परिणाम है कि हम लाखों करोड़ों रुपए की लागत के विकास कार्य 100 दिन के अंदर ही काफी आगे तक पहुंचाने में सफल रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का तीसरा कार्यकाल, अपने पहले 100 दिनों में, एक प्रभावशाली और सफल विकास यात्रा का प्रतीक बन गया है। ये 100 दिन केवल एक समयावधि नहीं, बल्कि एक ठोस नींव हैं, जो आने वाले पांच वर्षों में भारत को 'विकसित राष्ट्र' की दिशा में अग्रसर करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस अवधि में सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, गरीब कल्याण, कृषि सुधार और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए नीतिगत फैसले प्रमुख रहे।

> प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में, देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें नए बंदरगाह, सड़कें और हवाईअड्डों का निर्माण शामिल है

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की नई परिभाषा

प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में, देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें नए बंदरगाह, सड़कें और हवाईअड्डों का निर्माण शामिल है। महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट परियोजना, 76,200 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी।

गरीब और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवासों को मंजूरी दी गई है, जिससे वंचित वर्गों के सिर पर छत का सपना साकार हो रहा है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को उनके अपने कार्ड के अलावा 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा जिससे उनका कवरेज 10 लाख रुपए हो जाएगा। लगभग साढ़े 4 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ होगा और इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है।

युवाओं और किसानों के लिए सशक्तीकरण

भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मोदी सरकार लगातार मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ तक पहुंचाया गया है। यह हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत देने वाला है और साथ ही लाखों नौकरियों का सृजन भी करेगा। 75,000 नई मेडिकल सीटों का विस्तार किया गया है, जो हमारे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रही हैं।

पीएम पैकेज के तहत 2 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं का ऐलान किया गया, जिससे अगले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलेंगे। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, भत्ता और

एकमुश्त सहायता राशि 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य, 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार की दिशा में प्रगति, PLI स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और MSME के लिए दिया गया वित्तीय प्रोत्साहन भी युवाओं के लिए कारगर साबित होगा।

देश के किसान भाइयों के लिए सरकार ने नई योजनाओं और समर्थन मूल्य बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। हम न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे किसानों की समृद्धि में वृद्धि हो रही है। पिछले 100 दिनों में ही मोदी सरकार ने 9.3 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि खातों में भेजी। अभी तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को तीन लाख करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। खरीफ फसलों की एमसपी बढ़ाने से 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा।

मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए राहत

पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। सैलेरिड क्लास 17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। वहीं पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा भी बढ़ाकर 25,000 किया है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सौगात दी। 100 दिन में ही सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की शुरुआत की। इसके तहत 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए 'वन रैंक- वन पेंशन' योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदी को 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा में अभूतपूर्व निर्णय

देश में पहली बार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6350 करोड़ रुपए की नई योजना लाई गई। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को 4100 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम को 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक अर्बन फंड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, GLOF और अन्य आपदाओं की रोकथाम की ज़रूरतों को आपदा प्रबंधन अधिनियम पूरा करेगा। इसके लिए 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि लद्दाख में पांच नए जिले बनाए गए हैं। नारकोटिक्स की रोकथाम और सूचनाओं के लिए MANS हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए एक सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जा रही है।

मोदी सरकार के पहले 100 दिन देश में सुशासन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में निर्णायक रहे हैं। इन प्रयासों ने हर वर्ग को साथ लेकर विकास की एक अनूठी दिशा दी है। 'विकसित भारत' का सपना अब एक विचार मात्र नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है, और यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल हो। आइए, हम सब इस विकास यात्रा का हिस्सा बनें और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर साकार करें। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद हैं)

100 दिनों का परिवर्तनकारी नेतृत्व

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी शासन का प्रमाण

तरुण चुघ

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 3.0 के 100 दिन पूरे हुए हैं, हमें गर्व के साथ इस अवधि के असाधारण उपलब्धियों को देखना चाहिए। इन तीन महीनों में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति देखी गई है, जो भारत के सतत विकास और प्रगति की नींव रख रही है।

समग्र विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एनडीए सरकार ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक सुधारों, कृषि, रक्षा, और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। ये प्रयास न केवल तात्कालिक लाभ ला रहे हैं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के महत्वाकांक्षी विज़न को साकार करने के रास्ते पर भारत को ले जा रहे हैं।

भविष्य के लिए रखी जा रही है मजबूत नींव

प्रधानमंत्री मोदीजी ने एक उन्नत और विकसित भारत की नींव रखी है। उनका नेतृत्व, जो गतिशीलता और रणनीतिक दूरदर्शिता से भरा हुआ है, देश को अधिक समृद्धि की दिशा में प्रेरित और संचालित कर रहा है। एक राष्ट्र के रूप में हमें उनके दूरदर्शी शासन के लिए गहरा आभार व्यक्त करना चाहिए, जो भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।

विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उपलब्धियां, एनडीए 3.0 के तहत परिवर्तनकारी बदलावों पर बल देती हैं। सरकार की जन-केंद्रित नीतियों ने गरीबों, मध्यवर्ग, दलितों, हाशिए के समुदायों, युवाओं और महिलाओं सहित विभिन्न समूहों के लिए जीवन की सुगमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। ये पहलें समावेशी विकास और सामाजिक समानता के प्रति प्रतिबद्ध एक नेतृत्व का प्रतिबिंब हैं।

राष्ट्रीय प्रगति का एक मील का पत्थर

मोदी सरकार के पहले 100 दिन केवल एक मील का पत्थर नहीं हैं, ये इसके राष्ट्रीय प्रगति के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण हैं। साहसिक पहलों के माध्यम से सरकार ने सतत विकास की एक मजबूत नींव रखी है, जिसका सकारात्मक प्रभाव वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ेगा। इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अवधि में 15 लाख करोड़ के निवेश किए गए हैं, जो परिवर्तनकारी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं।

> सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश भारत की कनेक्टिविटी नेटवर्क को फिर से आकार दे रहा है, जो आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने, नए बंदरगाहों के निर्माण और रेलवे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है

कृषि: विकास के केंद्र में

मोदी सरकार का कृषि पर फोकस, आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। किसानों को अपनी आर्थिक दृष्टि के केंद्र में रखते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उनकी भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। हाल ही में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि ने किसानों की आय को बढ़ाने में कारगर भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही, प्याज और बासमती चावल जैसे प्रमुख उत्पादों पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को हटाना सरकार की कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 20,000 करोड़ का वितरण किया गया है, जिससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ मिला है, ये प्रधानमंत्री मोदीजी की ग्रामीण आजीविकाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है।

बुनियादी ढांचे का विकास: आर्थिक विकास की शक्ति

सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश भारत की कनेक्टिविटी नेटवर्क को फिर से आकार दे रहा है, जो आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने, नए बंदरगाहों के निर्माण और रेलवे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

एक दूरदर्शी विज़न प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE)

योजना में दिखाई देता है, इस योजना के लिए 10,900 करोड़ का बजट रखा गया है, जो भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास को तेज़ गति दे रहा है, इसके साथ ही ये कदम परिवहन के क्षेत्र में स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा को मजबूत करना

मोदी 3.0 में भारत की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। रक्षा खरीद के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये के समर्पित बजट के साथ सरकार राष्ट्र की सुरक्षा संरचना को बेहतर बना रही है।

इसके अलावा, 'वन रैंक वन पेंशन' (ओआरओपी) योजना का सफल क्रियान्वयन रक्षाकर्मियों और उनके कल्याण के प्रति सरकार के समर्थन को मजबूत करता है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार के अडिग रुख ने जम्मू और कश्मीर में शांति को स्थापित किया है।

समुदायों को सशक्त बनाना और सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाना

ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं ने लाखों लोगों विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ से अधिक घरों को स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 5.36 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को लाभ मिलेगा।

मध्यम वर्ग, जो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है, को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कर सुधारों की शुरुआत की है, जिसमें 7 लाख तक की आय कर मुक्त और मानक कटौती में वृद्धि शामिल है।

महिलाओं का सशक्तीकरण: सतत विकास का सहायक

मोदी सरकार मानती है कि महिलाओं का सशक्तीकरण सतत विकास के लिए अति आवश्यक है। विभिन्न पहलों के माध्यम से, 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों और कौशल विकास के अवसरों तक पहुंच मिली है। 11 लाख नई 'लखपति दीदियों' को बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी की महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा, मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर महिला उद्यमियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने में सक्षम बना रहा है।

> विभिन्न पहलों के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों और कौशल विकास के अवसरों तक पहुंच मिली है। 11 लाख नई 'लखपति दीदियों' को बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी की महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा, मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर महिला उद्यमियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने में सक्षम बना रहा है

युवा शक्ति का मंथन

भारत के युवा हमारे भविष्य की रीढ़ हैं, और सरकार उनके विकास में भारी निवेश कर रही है। कौशल संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज पेश किया गया है, जिसमें प्रथम बार कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन भी शामिल है। यह पहल कौशल अंतर को पाट रही है, उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि अगली पीढ़ी भारत के आर्थिक पुनरुत्थान का नेतृत्व करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित रहे।

स्वास्थ्य और शिक्षा: मौलिक अधिकार, मौलिक प्रगति

सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में प्राथमिकता दी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी नागरिक आवश्यक सेवाओं से लाभान्वित हों। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का विस्तार करके 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे 4.5 करोड़ परिवार और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, मेडिकल के क्षेत्र में 75,000 सीटों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में दूरगामी सुधार देखने को मिलेंगे और विदेशी संस्थानों पर निर्भरता कम होगी।

न्यायिक सुधार: एक नए युग के लिए

नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ सरकार ने तीन नए आपराधिक कानून पेश किए हैं जिनका उद्देश्य न्याय पर ध्यान केंद्रित करना है। ये कानूनी सुधार, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के माध्यम से पुराने औपनिवेशिक और अंग्रेजों के समय के बने कानूनों को प्रतिस्थापित करते हैं, जिसका उद्देश्य न्याय को अधिक सुलभ, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES), जिसके लिए 2,250 करोड़ रुपये का बजट है, समय पर और वैज्ञानिक साक्ष्य जांच सुनिश्चित करके न्याय प्रणाली को और मजबूत कर रही है।

अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में एक नई शुरुआत

भारत की अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में

प्रगति नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जिसमें अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए 1,000 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की गई है। यह पहल भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है, जो वैश्विक मंच पर नवाचार और सहयोग के लिए नए अवसर खोलती है।

एक दूरदर्शी नेता, एक समृद्ध भविष्य

ये विदित है की इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री मोदीजी के विज़न ने भारत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

व्यापक कृषि सुधारों और विशाल अवसंरचना विकास से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सभी भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की नीति महत्वपूर्ण रही है। एनडीए सरकार ने राष्ट्र के भविष्य को बेहतर बनाने के अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

वर्तमान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी के कूटनीतिक प्रयास सराहनीय रहे हैं, जो वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन संघर्षों पर उनकी गहरी चिंता और संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांति बहाल करने के लिए भारत की हरसंभव सहायता प्रदान करने पर जोर उनके शांति समाधान खोजने के प्रति समर्पण को उजागर करता है। मोदीजी का दृष्टिकोण भारत की भूमिका को एक जिम्मेदार वैश्विक देश के रूप में रेखांकित करता है, जो शत्रुता को समाप्त करने और कूटनीतिक समझौतों के महत्व की वकालत करता है। उनके प्रयासों को व्यापक रूप से मान्यता मिली है और नेताओं ने शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका की सराहना की है। निःसंदेह 'वसुधैव कुटुंबकम' के मंत्र के साथ मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में सामने आकर भारत को 'विश्वगुरु' बना रहे हैं।

भारत 'विकसित देश' की ओर अग्रसर है, जो प्रौद्योगिकी उन्नति, उद्योग-हितैषी नीतियों और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता की एक अडिग सोच द्वारा संचालित है। देश एक समृद्ध भविष्य की दहलीज पर खड़ा है, जो वैश्विक मंच पर अपनी उचित जगह लेने के लिए तैयार है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है: शिवराज सिंह चौहान

मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय लिया; सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 सितंबर को कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसान हितैषी हैं। कृषि व किसान कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी सरकार ने किसानों के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी मोदी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा। इस कदम से सभी तिलहन किसानों ख़ासतौर से सोयाबीन और मूंगफली के किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे, जिनकी फसल अभी बाज़ार में आने वाली है। साथ ही, रबी में तिलहन की बुवाई में बढ़ोतरी होगी और सरसों की फसल के भी अच्छे दाम मिल पायेंगे।

श्री चौहान ने कहा कि किसान कल्याण के प्रति संवेदनशील मोदी सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय भी लिया है। निर्यात शुल्क के हट जाने से बासमती उत्पादक किसानों को अपनी उपज के ठीक दाम मिलेंगे और बासमती चावल की मांग बढ़ने के साथ ही निर्यात में भी वृद्धि होगी। किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने रिफाइन ऑयल के लिए मूल शुल्क (बेसिक ड्यूटी) को 32.5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से रिफाइनरी तेल के लिए सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली की फसलों की मांग बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि किसानों को इन फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे। साथ ही, छोटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिफाइनरी बढ़ने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की प्रगति के प्रति संकल्पित मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। निर्यात शुल्क के कम हो जाने से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलेंगे और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय से किसानों के साथ प्याज से जुड़े अन्य सेक्टर्स/क्षेत्रों को भी सीधा लाभ मिलेगा। ■

प्रधानमंत्री ने ओडिशा में महिला-केंद्रित सबसे बड़ी योजना 'सुभद्रा' का किया शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना 'सुभद्रा' का शुभारंभ किया। यह महिला-केंद्रित सबसे बड़ी योजना है और इसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में धन राशि का अंतरण भी किया। श्री मोदी ने 2800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया तथा 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने लगभग 14 राज्यों के पीएमएवाई-जी के तहत लगभग 10 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की, देश भर से पीएमएवाई (ग्रामीण और शहरी) के 26 लाख लाभार्थियों के लिए गृह-प्रवेश समारोह में हिस्सा लिया और पीएमएवाई (ग्रामीण और शहरी) लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी। इसके अलावा, उन्होंने पीएमएवाई-जी के लिए अतिरिक्त परिवारों के सर्वेक्षण के लिए आवास+2024 ऐप और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के परिचालन दिशानिर्देश भी जारी किए।

श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि लोगों और भगवान जगन्नाथ की सेवा करने का अवसर तब मिलता है, जब भगवान का आशीर्वाद मिलता है।

प्रधानमंत्री ने गणेश उत्सव और आज अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां भगवान विश्वकर्मा के रूप में कौशल और श्रम की पूजा की जाती है। श्री मोदी ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे पवित्र अवसर पर उन्हें ओडिशा की माताओं और बहनों के लिए सुभद्रा योजना शुरू करने का अवसर मिला है।

श्री मोदी ने आज भगवान जगन्नाथ की धरती से देशभर में 30 लाख से अधिक परिवारों को पक्के मकान सौंपे जाने का जिक्र किया और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख और शहरी क्षेत्रों में 4 लाख मकान सौंपे गए हैं। उन्होंने आज ओडिशा में हजारों करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए ओडिशा और देश के लोगों को बधाई दी।

श्री मोदी ने कहा कि नई भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह उनकी पहली ओडिशा यात्रा है, जिसके शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल हुए थे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर 'डबल इंजन' वाली सरकार बनती है, तो ओडिशा प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। श्री मोदी ने विश्वास जताया कि ग्रामीणों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के सपने अब पूरे होंगे। उन्हें खुशी है कि किए गए वादे तेजी से पूरे हो रहे हैं।

श्री मोदी ने 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में धन राशि का अंतरण किया

अब तक पूरे किए गए वादों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर के सभी चार द्वार जनता के लिए खोल दिए गए हैं और मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ओडिशा के लोगों की सेवा के लिए प्रयासरत है और उन्होंने खुशी जताई कि सरकार खुद लोगों के पास जाकर उनके मुद्दों को हल करने जा रही है। श्री मोदी ने इसके लिए पूरी ओडिशा सरकार को बधाई दी और उसकी प्रशंसा की।

अपने संबोधन के समापन पर प्रधानमंत्री ने ओडिशा और देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का भरोसा जताया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में विकास की गति और तेज होगी।

इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल श्री रघुबर दास और मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ■

सिखों को पुनः निराश किया

अपनी विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों ने न केवल सिख समुदाय को बल्कि सभी भारतीयों को निराश और हताश किया है

हरदीप सिंह पुरी

राहुल गांधी की अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत के सिखों को लेकर की गयी हालिया टिप्पणियों ने न केवल सिख समुदाय को बल्कि सभी भारतीयों को निराश और हताश किया है। एक गौरवशाली सिख के रूप में, जिसने 62 वर्षों तक पगड़ी पहनी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहां किसी भी सिख को इस बात को लेकर कोई पशोपेश नहीं है कि 'क्या भारत में एक सिख को अपनी पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या वह एक सिख के तौर पर गुरुद्वारा जाने में समर्थ होगा।' गौरतलब है कि राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में एक 'टॉक शो' के दौरान इन बातों का जिक्र किया था। उनका तर्क इतना विचित्र और सभी सिखों के जीवित अनुभव से अलग है कि यह समझ से परे है।

मैंने पहले राजनयिक के रूप में और अब कैबिनेट के सदस्य के रूप में पांच दशकों से अधिक समय तक भारत की सेवा की है। सिख भारत को अपनी मातृभूमि और अपनी कर्मभूमि मानते हैं। गांधी के दुर्भावनापूर्ण और विभाजनकारी प्रचार को पनपने नहीं दिया जा सकता। इस शरारत को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की बात कही है, पिछले साल कैम्ब्रिज में उन्होंने सिखों को भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक कहा था।

भारत में सिखों को असुरक्षित महसूस करने और अस्तित्व के लिए खतरा महसूस करने का एकमात्र मौका 1980 के दशक की शुरुआत में आया था और गांधी को इस बारे में खुद को शिक्षित करने की जरूरत है। उनके बयान से एक स्वाभाविक सवाल उठता है: क्या राहुल गांधी अपने परिवार एवं पार्टी द्वारा सिखों पर किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगेंगे? यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था, जिसमें हरमंदिर साहिब परिसर पर बेशर्मी से हमला किया गया और अकाल तख्त को नष्ट करके सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल को नष्ट करने का प्रयास किया गया था? क्या वह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई हिंसा के लिए माफी मांगेंगे, जब कांग्रेस के गुंडों ने 3,000 सिखों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसमें से ज्यादातर दिल्ली में हुई थी? क्या वह अपने पिता राजीव गांधी की निंदा करेंगे, जिन्होंने अत्याचारों के बाद कहा था कि 'जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो जमीन हिलती है', क्या इस तरह की जघन्य हिंसा किसी भी तरह से कानून के शासन वाले लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए उचित थी?

> **क्या राहुल गांधी अपने परिवार एवं पार्टी द्वारा सिखों पर किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगेंगे? यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था, जिसमें हरमंदिर साहिब परिसर पर बेशर्मी से हमला किया गया और अकाल तख्त को नष्ट करके सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल को नष्ट करने का प्रयास किया गया था?**

मुझे संदेह है कि हमें इस माफी के लिए लंबे समय तक इंतजार करना होगा। यह तथ्य कि उनके बयानों को हाशिये पर पड़े अलगाववादी लोगों ने समर्थन दिया है, कुछ असहज सवाल खड़े करता है जिसका जवाब गांधी को देना चाहिए। वह उन्हें यूं ही खारिज नहीं कर सकते, जैसाकि उनके सबसे करीबी सलाहकार सैम पित्रोदा ने सिखों के खिलाफ की गई हिंसा के बारे में कहा था, 'हुआ तो हुआ'।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इन घावों को भरने का प्रयास किया है। सिख शिक्षाओं, विशेष रूप से एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रति प्रधानमंत्री की श्रद्धा, सरकार के अधिकांश कार्यों में स्पष्ट है। हम सिख समुदाय की निष्ठा, ईमानदारी और कड़ी मेहनत का सम्मान करते हैं। पिछले 10 वर्षों में सिख समुदाय के कल्याण और लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं, जो कांग्रेस के शासन से बिल्कुल भिन्न है।

यह मोदी सरकार ही थी जिसने 312 सिखों को ब्लैक लिस्ट या 'केंद्रीय प्रतिकूल सूची' से हटाया गया, जिसे कांग्रेस की सरकार द्वारा जारी किया गया था। पंजाब में अशांति के दौरान सरकारी उत्पीड़न के कारण विदेशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे सिख हमारे हस्तक्षेप के कारण घर वापस आ पाए। यह मोदी सरकार ही थी जिसने 1984 के अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए कदम उठाए और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी।

यह मोदी सरकार ही थी जिसने श्री दरबार साहिब, अमृतसर के लिए एफसीआरए पंजीकरण की सुविधा प्रदान की एवं लंगर तथा लंगर की वस्तुओं को कर-मुक्त बनाया। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो मोदी सरकार ने 230 सिख परिवारों की वतन वापसी एवं पवित्र गुरुग्रंथ साहिब की पांच प्रतियां को सुरक्षित वापस लाने के लिए कदम उठाया। मोदी सरकार ने नवंबर, 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर

का उद्घाटन किया। यह मोदी सरकार ही थी जिसने गुरु नानकदेव जी के 550वें प्रकाश पर्व के साथ-साथ गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव एवं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को पूरे भारत तथा दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया। यह मोदी सरकार ही थी जिसने घोषणा की कि 26 दिसंबर को 'छोटे साहिबजादों' के सम्मान में वीर बल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार एक ऐतिहासिक गलती को सुधार कर सिख परंपरा को गौरव प्रदान किया।

इसके विपरीत, कांग्रेस ने सिखों को अपमानित करने और उनका अनादर करने के अलावा क्या किया? राहुल गांधी को कांग्रेस के इतिहास के काले अध्यायों के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी लेनी चाहिए। अगर कभी सिखों को पहचान के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो वह कांग्रेस के शासन में और जो पार्टी के स्पष्ट दिशानिर्देशों के तहत हुआ था। 1982 में पुलिस ने सिखों को बसों और कारों से घसीटकर नीचे उतारा, उनकी पगड़ी और कड़ा से उनकी पहचान की, ताकि उन्हें 1982 के एशियाई खेलों से पहले दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके, क्योंकि कांग्रेस नेताओं द्वारा इस समुदाय को 'खतरा' माना जाता था। यही वही विरासत है, जिससे गांधी को अब जूझना होगा।

अमेरिका में राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। ■

(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं)

प्रधानमंत्री ने झारखंड में कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया

संपर्क बढ़ाने के लिए छह वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए झारखंड के टाटानगर में 660 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 32 हजार लाभार्थियों को मंजूरी पत्र भी वितरित किए। इससे पहले श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर छह वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ और भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन करने के साथ की। उन्होंने झारखंड में कर्मा पर्व के पवित्र अवसर का भी उल्लेख किया, जिसे प्रकृति की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। साथ ही श्री मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे पर उनके लिए किए गए स्वागत की कुछ भी जानकारी भी दी, जहां एक महिला ने उन्हें कर्मा पर्व का प्रतीक भेंट किया। उन्होंने कहा कि कर्मा पर्व के तहत महिलाएं अपने भाइयों के सुखी जीवन की कामना करती हैं।

इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज झारखंड को छह नई वंदे भारत ट्रेनों, 600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं और पीएम आवास योजना के तहत राज्य के लोगों के लिए पक्के घरों की सौगात मिली है। श्री मोदी ने इन परियोजनाओं के लिए झारखंड के लोगों और इन वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से कनेक्टिविटी पाने वाले अन्य राज्यों को भी बधाई दी।

उस समय को याद करते हुए, जब आधुनिक विकास केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित था और झारखंड जैसे राज्य पीछे छूट गए थे, श्री मोदी ने कहा कि, 'सबका साथ सबका विकास' के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। उन्होंने कहा, "देश की प्राथमिकताएं गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, महिलाएं, युवा और किसान हैं।"

प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र ने झारखंड की समग्र प्रगति और विकास सुनिश्चित करने के लिए निवेश बढ़ाने के साथ-साथ विकास कार्यों की गति भी बढ़ा दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए झारखंड को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी गई, जो 10 साल पहले आवंटित बजट की तुलना में 16 गुना अधिक है। ■

भारत के पैरालंपिक चैंपियनों ने अब तक के सर्वाधिक पदक जीतकर एक नया मानक स्थापित किया है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस में हुए पैरालंपिक खेलों में भारतीय पैरा-एथलीटों के रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद नई दिल्ली में 12 सितंबर, 2024 को अपने आवास पर उनसे मुलाकात की।

भारतीय पैरालंपिक दल 'सिटी ऑफ लाइट' में शानदार प्रदर्शन करने के बाद घर लौट आया, जिसने 7 स्वर्ण सहित कुल 29 पदक जीते। इस प्रकार भारत ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में हासिल किए गए अपने पिछले सर्वोच्च पैरालंपिक पदकों को 10 पदकों से पीछे छोड़ दिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने 'एक्स' अकाउंट पर 13 सितंबर को पोस्ट किए गए एक वीडियो में भारतीय पैरालंपिक दल से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ श्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि भारत के पैरालंपिक चैंपियनों ने अब तक के सर्वाधिक पदक जीतकर एक नया मानक स्थापित किया है। उनके साथ बातचीत करना एक खुशी की बात थी। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

इंडिया एक्सपो मार्ट (ग्रेटर नोएडा) में 11 सितंबर, 2024 को सेमीकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन के अवसर पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 12 सितंबर, 2024 को पेरिस पैरालंपिक 2024 में शामिल भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत मंडपम (नई दिल्ली) में 12 सितंबर, 2024 को नागरिक उड्डयन पर आधारित दूसरे एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में प्रदर्शनी का अवलोकन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

टाटानगर (जमशेदपुर) में 15 सितंबर, 2024 को विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखते एवं उन्हें राष्ट्र को समर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गांधीनगर (गुजरात) में 16 सितंबर, 2024 को चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो (री-इनवेस्ट) का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भुवनेश्वर (ओडिशा) में 17 सितंबर, 2024 को सबसे बड़ी महिला-केंद्रित योजना 'सुभद्रा' और अन्य विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 01 अक्टूबर, 2024
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह